श्री अली अनवर : सर, ...(**व्यवधान**)... सर ये योजनाएं ...(**व्यवधान**)... सर, वीवर्स सुसाइड कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)... खुदकुशी कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप मेरी बात सुनिए ...(**व्यवधान**)... hear me ...(**व्यवधान**)... मेरी बात सुनिए ...(**व्यवधान**)... ये सुसाइड कर रहे हैं या कोई और बात है, तो आप दूसरा क्वैश्चन देते। ...(**व्यवधान**)... इस क्वैश्चन के बारे में दूसरे फॉर्म में आ सकते हैं ...(**व्यवधान**)... यह तो मैं अलाउ नहीं करुंगा ...(**व्यवधान**)... क्वैश्चन-204 ...(**व्यवधान**)... वह ठीक आया ...(**व्यवधान**)...। I understand your problem. ...*(Interruptions)*... Mr. Raghavan, I understand your problem. *(Interruptions)* आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा ...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record. *(Interruptions...* ठीक है, ठीक है ...(**व्यवधान**)... मेरी बात तो सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)... मैं अलाउ नहीं करुंगा। ...(**व्यवधान**)... देखिए, आपका क्वैश्चन ...(**व्यवधान**)... एक मिनट ठहरिए ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, आप बैठिए तो सही ...(**व्यवधान**)... क्वैश्चन करने वाले केरल के थे ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... Please take your seat ...(**व्यवधान**)... Please take your seat ...(**व्यवधान**)... क्वैश्चन करने वाले केरल के थे। वे माननीय सदस्य केरल के हैं। इसलिए मैं सिर्फ केरल को ही अलाउ करुं और आन्ध्र प्रदेश को अलाए नही करुं, तो कैसा लगेगा? ...(**व्यवधान**)... नही, आप क्वैश्चन दोबारा कर लीजिए ...(**व्यवधान**)... इस क्वैश्चन में नहीं ...(**व्यवधान**)... आप दोबारा क्वैश्चन कर लीजिए या दूसरे किसी भी फॉर्म में आ जाइए ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, ...(**व्यवधान**)... प्रश्न संख्या 204 ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. I won't allow it. Nothing will go on record. Please take your seat. Question No. 204.

रक्षा सौदों में ईमानदारी और पारदर्शिता

*204. **श्री बशिष्ठ नारायण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा सौदों की खरीद में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीति का बयौरा क्या है;

(ख) रक्षा बजट के लिए आबंटित राशि के समय पर व्यय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है

(ग) क्या यह सच है कि आबंटित राशि की एक बड़ी मात्रा समय पर खर्च नहीं हो पाती है; और

(घ) रक्षा उपकरणों के निर्यात में देशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. अन्तोनी) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी-2006) तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैंनुअल (डी पी एम-2006) 01 सिंतबर, 2006 से प्रख्यापित हुए हैं। डी पी पी 2006 में रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सभी पूंजीगत अर्जन (चिकिस्ता उपस्कर को छोड़कर) शामिल हैं। डी पी एम-2006 में रक्षा मंत्रालय की चिकित्सा उपस्कर अधिप्राप्ति सहित राजस्व अधिप्राप्तियां शामिल हैं।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं का उद्देश्य, आबंटित बजटीय संसाधनो का इष्टतम इस्तेमाल करके निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित क्षमताओं के संबंध में सशस्त्र सेनाओं की अनुमोदित जरुरतों की शीघ्र अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करते समय, इन प्रक्रियाओं में उच्च दर्जे की ईमानदारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यों में पारदर्शिता,स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता प्रदर्शित होगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में शामिल किए गए प्रावधानों में ये शामिल है:- (i) 100 करोड़ रुपए से अधिक की सभी संवीदाओं के लिए सरकारी विभाग और बोलीदाता के बीच ‘सत्यनिष्ठा संबंधी समझौता ‘; (ii) मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओ ई एम) या प्राधिकृत विक्रेताओं या सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों के साथ सीधा कारबार करना (ऎसे देशों मामले में लागू जहां के घरेलू कानून मूल उपस्कर विनिर्माताओं को सीधे निर्यात की अनुमति नहीं देते); (iii) अधिग्रहंण प्रक्रिया में बड़े निर्णय सामूहिक (कालेजिएट) तरीके से लेना; (iv) फिल्ड परीक्षण करने में और अधिक पारदर्शिता; (v) विक्रेताओं के साथ बोली-पूर्व बैठकें; (vi) सरकार से कोई संविदा प्राप्त करने हेतु विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाना; (vii) विक्रेता को संविदा प्राप्त करने के लिए सरकार से सिफारिश करने हेतु किसी व्यक्ति अथवा फर्म की नियुक्ति पर तथा ऎसी किसी सिफारिश के लिए धनराशि का भुगतान किए जाने पर रोक लगाना।

डी पी पी-2006 तथा डी पी एम-2006, दोनो ही, रक्षा मंत्रालय की बेवसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्य. एम ओ डी@ एन आई सी. इन) पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं ताकि इन तक आसानी से पहुंचा जा सके तथा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों के बारे में लोक-जागरुकता बढ़ सके।

रक्षा बजट संबंधी व्यय की रक्षा मंत्रालय द्वारा निकट से तथा नियमित रुप से मानीटरिंग की जाती है और आबंटित निधियों का इष्टतम इस्तेमाल हुआ है। इसलिए,आबंटित राशि के बड़े भाग के बिना खर्च किए पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों(डी पी एस यू एस) तथा निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित मदों के निर्यात में सुधार लाने के लिए की गई पहल में ये शामिल हैः (i) लक्षित देशों में निर्यात-घरानो की स्थापना की समीक्षा; (ii) निर्यात के अवसरों की पहचान करने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात अताशों को सक्रिय रुप से शामिल करना; (iii) उत्पादन युनिटो, विदेश मंत्रालय तथा सेना मुख्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सार्वजिनिक क्षेत्रों के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माण बोर्ड में नाडल अफसरों की नियुक्त; (iv) विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से भारतीय रक्षा उत्पादों तथा सी डी रोमों की निर्देशिका का वितरण; (v) डीफेक्स्यो इंडिया तथा एयरो इंडिया जैसी द्विवार्षिक अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन; और (vi) डी पी पी-2006 के अनुसार सीधे क्षतिपूर्ति (आफसेट) संबधी उपबंधों को लागू करना।

Honesty and transparency in Defence deals

†*204. SHRI BASHISTHA NARAIN SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the details of the policy of Government to ensure honesty and transparency in Defence deals;

(b) the efforts being made by Government to ensure timely spending of money allocated in Defence budgets;

(c) whether it is a fact that a large chunk of the allocated amount remains unspent; and

(d) the details of the plan of Government to encourage indigenous industry to carry out exports in the field of Defence equipments?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): (a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Defence Procurement Procedure (DPP-2006) and Defence Procurement Manual (DPM-2006) have been promulgated with effect from 1st September, 2006. DPP 2006 covers all Capital Acquisitions (except medical equipment) undertaken by the Ministry of Defence. DPM-2006 covers Revenue Procurement including Medical equipment procurement of the Ministry of Defence.

The objective of Defence Procurement Procedures is to ensure the expeditious procurement of approved requirements of the Armed Forces in

†Original notice of the question was received in Hindi.

terms of capabilities sought within time frames prescribed by optimally utilizing allocated budgetary resources. While achieving this objective, these procedures would demonstrate the highest degree of probity and public accountability, transparency in operations, free competition and impartiality. The provisions incorporated in Defence Procurement Procedures for achieving this objective include; (i) An 'Integrity Pact between the Govemment department and the bidder for all contracts above Rs. 100 crores; (ji) Dealing directly with Original Equipment Manufacturers (OEM) or-Authorised vendors or Government Sponsored export Agencies (applicable in case of countries where domestic laws do not permit direct export by OEMs); (iii) Major decisions in the acquisition process being taken in a 'Collegiate' manner; (iv) Enhanced trasparency in the conduct of field trails; (v) Pre-bid meetings with vendors; (vi) Prohibiting the use of undue influence by the seller for obtaining any contract with the Govemment; (vii) Prohibiting the engagement of any individual or firm to recommend to the Government the award of a contract to the seller, and the payment of any amount in respect of any such recommendation.

Both the DPP-2006 and DPM-2006 have been placed on the website of the Ministry of Defence (www.mod.@nic.in) for enabling ease of access and increased public awareness of defence procurement procedures and processes.

The expenditure on defence budget is closely and regularly monitored by the Ministry of Defence and there has been optimal utilization of allocated funds. Therefore, the question of a large chunk of the allocated amount remaining unspent, does not arise.

Initiatives taken to improve export of items produced by Ordinance Factories, Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) and private companies include (i) review of setting up of Export Houses in target countries; (ii) active involvement of Defence Attacthes posted in Indian Missions abroad in identifying export opportunities; (iii) appointment of nodal officers in DPSUs and the Ordnance Factory Board for better coordination between production units, Ministry of External Affairs and Service Headquarters; (iv) distribution of Directory of Indian Defence Products and CD ROMs through Indian Missions abroad; (v) organization of biennial international exhibitions *viz.* Defexpo India and Aero India; and (vi) implementation of Direct Offset Provisions as per DDP-2006.

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि रक्षा उपकरण, जो स्वदेश में बन सकते हैं और जिनका आयात बाहर के देशों से होता है, क्या सरकार ने इसका आइडेंटिफिकेशन किया है कि इस देश में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन औजारों का निर्माण इस देश में हो सकता है? यदि सरकार ने पता लगा लिया है कि इनको भारतीय उद्योगों में उत्पादित किया जा सकता है, तो इसके लिए सरकार ने क्या पहल की है?

SHRI A.K. ANTONY: Regarding indigenous production, Government is very clear. As far as possible, we must encourage indigenous production. But, wherever there is shortage, we will import because we have to meet the requirements of the Armed Forces also. The new procurement policy lays down that 30 percent of the expenditure should be off-set. So, in any project which is beyond Rs. 300 crores, thirty per cent off-set is there. That also will help indigenous industries.

श्री बशिष्ट नारायण सिंह : सभापति महोदय, भारत में सुरक्षा को लेकर बजट उपबंध की चर्चा मैंने अपने प्रश्न में की है, क्योकि अभी भारतीय सीमा पर सुरक्षात्मक उपायो पर कई सवाल उठ रहे हैं। देश के नक्शे के संबंध में, कभी-कभी सीमा और देश की सुरक्षा को लेकर सवाल सदन में भी उठते रहे है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अपने रक्षा बजट का कोई खर्चा, विशेषकर सीमा की सुरक्षा पर कोई करने का निर्णय किया गया है?

SHRI A. K. ANTONY: Sir, the Defence funds are spent as per the Budget Estimates. So far, from 2001 to 2005-06, we are spending from 95 per cent to 98 per cent of these funds. As far as border areas are concerned, we will take care of it.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, the Defence Procurement Procedure 1992 states that so far the defence procurement is concerned, publicity should be given through open advertisement and through trade journals. Also, the representation of the HAL, Director General-Aeronautical Quality Assurance, Centre for Military Airworthiness and Certification is necessary in the defence procurement procedure. Sir, in September, 2003, the Defence Ministry contracted for procurement of five executive jets at a cost of Rs. 712.51 crores. This item is non-defence in nature. I want to know from the hon. Minister whether the prescribed procedure of the Defence Ministry was followed in this particular case or not.

SHRI A.K. ANTONY: Sir, the hon. member should give a separate question for this, and then only I can answer this question.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, the question is relating to honesty and transparency in defence deals ...*(Interruptions)*... It is relating to honesty and transparency in defence deals. ...*(Interruptions)*... The procedure was...*(Interruptions)*... to get the transparency...*(Interruptions)*...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, the hon. Minister is evading the answer... *(Interruptions)*...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: What is this, Sir? ...*(Interruptions)*... It is related with transparency. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.K.ANTONY: I will answer it. I have nothing to hide and nothing to evade also. The present Government improved the defence procurement procedure. As per the new procedure adopted in 2006. transparency is there, and ...*(Interruptions)*...

SHRI MOINUL HASSAN: The question is about the year 2003. ...*(Interruptions)*... It is relating to the previous Government. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister is not answering the question.

SHRI A.K. ANTONY: As per the new procedure, not only everything is published in paper, everything is...

SHRI MOINUL HASSAN: We are talking about the procedure followed in 2003 ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister speak ...*(Interruptions)*... Please take your seat ...*(Interruptions)*...

SHRI A.K. ANTONY: You see, there was a time when defence procurement was classified and secret. In the present Government, now the policy is, everything is even published...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Please answer about 2003.

SHRI A. K. ANTONY: I will answer it...*(Interruptions)*... As per the present policy, everything is even given on the website. But, as far as the particular question of the hon. Member is concerned, I need a separate question for that. Then only I can answer that.

श्री अमर सिंह : माननीय सभापति महोदय, एक ओर तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने रक्षा सामान की खरीद के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य

दिया है कि रक्षा सौदे में एजेंटों से बचना मुमकिन नहीं है और उनकी नियुक्ति की विधिवत व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपके माध्यम से सम्मानीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंग कि सरकार ने एजेंटों की नियुक्ति के लिए क्या कोई नियम बनाए हैं या सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग की संस्तुति के अनुसार रक्षा सामान खरीद रही है?

SHRI A.K. ANTONY: Sir, the new Defence Procurement Policy was adopted after going through the guidelines of the CVC, the CAG and also the Standing Committees. So, we have gone through everything.

The new procedure is adopted as per the guidelines only. So, we are concerned about the transparency, but the present Policy categorically says that there is no middleman in it.

Fratricide among armed forces

*205. SHRI O.T. LEPCHA:
SHRI SANTOSH BAGRODIA:††

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) in which areas majority of cases of fratricide among armed forces had taken place during the recent years;

(b) whether Government have gone into the causes of such cases;

(c) the steps taken to improve service conditions of the armed personnel, posted in disturbed areas;

(d) whether it is a fact that lack of social security to the families of soldiers has led them to take such extreme step; and

(e) if so, what steps are being taken by Government to improve the welfare measures for their families?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) Most of the recent cases of fratricide among Armed Forces have taken place in Jammu & Kashmir and the North East region where Army is engaged in counter insurgency operations.

††The question was actually asked on the floor of the House by [Shri Santosh Bagrodia].